श्री मोहन चौधरी

बनाम

द चीफ कमिश्नर, यूनियन

त्रिपुरा क्षेत्र

(बी. पी. सिन्हा सी. जे., के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह,

रघुबर दयाल और जे. आर. मुधोलकर जे.)

मौलिक अधिकार- आपातकालीन निरोध की घोषणा- उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार- भारत के संविधान का निलंबन, कला 21, 22 और 32- राष्ट्रपति का आदेश डीटी। 3 नवंबर, 1962- सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), 8- भारत का रक्षा अध्यादेश, 1962 (1962 का 4)- भारत का रक्षा अधिनियम, 1962 (1962 का 51), धारा 48

26 अक्टूबर, 1962 को राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी। उसी दिन उन्होंने भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 और धारा 3 के तहत जारी किया। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1962 जारी किए। 3 नवंबर, 1962 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति के किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा के दौरान "यदि ऐसे व्यक्ति को भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है"। 20 नवंबर, 1962 को प्रतिवादी ने धारा 30 के तहत एक आदेश दिया। याचिकाकर्ता के निरोध के लिए भारत के रक्षा नियमों का याचिकाकर्ता ने अपनी नजरबंदी को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि याचिका विचारणीय नहीं थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार एक गारंटीकृत अधिकार होने के कारण इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है और इस अधिकार को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश अप्रभावी था क्योंकि यह अध्यादेश के निरंतर अस्तित्व पर निर्भर था लेकिन अध्यादेश को भारत रक्षा अधिनियम, 1962 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

अभिनिर्धारित किया कि याचिका विचारणीय नहीं थी। हालाँकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को छुआ नहीं गया था, लेकिन इस तरह के रिट के लिए अदालत का रुख करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। आदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए एक नागरिक के सभी अधिकारों को निलंबित नहीं किया, बल्कि केवल 21 और 22 के तहत अधिकारों को निलंबित कर दिया। चूंकि न्यायालय में जाने का उनका अधिकार निलंबित कर दिया गया था, इसलिए वे अधिनियम और नियमों के अधिकारों को चुनौती देने के हकदार नहीं थे। भारत रक्षा अधिनियम, 1962 द्वारा अध्यादेश के निरसन ने राष्ट्रपति के आदेश को अप्रभावी नहीं बनाया। धारा 48 में बचत धारा के आधार पर, अधिनियम के "अध्यादेश के तहत किए गए किसी भी नियम या की गई कोई कार्रवाई" को अधिनियम के तहत किया गया या किया गया माना जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति के आदेश में अध्यादेश का संदर्भ, धारा 8 के आधार पर था। सामान्य धारा अधिनियम, जिसे अधिनियम के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना है। धारा 8 में "इंस्ट्रूमेंट" शब्द, इसमें राष्ट्रपति का आदेश भी शामिल था।

मूल न्यायनिर्णयः बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं. 15/1963

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हेबियास कार्पस याचिका।

आर. के. गर्ग, याचिकाकर्ता की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से एस. वी. गुप्ता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर- जनरल डी. आर. प्रेम, आर. एच. ढेबर और आर. एन. सचथे।

एस. सी. अग्रवाल, आर. के. गर्ग, एम. के. राममूर्ति और डी. पी. सिंह, मध्यस्थ के लिए।

न्यायालय का निर्णय 29 अप्रैल 1963 को सिन्हा सी. जे. द्वारा सुनाया गया था।

26 अक्टूबर, 1962 को राष्ट्रपति को इस बात का संतोष हुआ कि एक गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल मौजूद है। जिसके द्वारा भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को चीनी आक्रामकता से खतरा है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हुए एक घोषणा जारी की गई। आपातकाल की घोषणा 8 नवंबर, 1962 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई थी और 13 नवंबर, 1962 को राज्यसभा और 14 नवंबर, 1962 को लोकसभा द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के बाद, क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और जैसा कि राष्ट्रपति संतुष्ट थे कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद थीं जो उनके लिए सी. एल. द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती थीं। संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के तहत , उन्होंने उसी तारीख- 26 अक्टूबर, 1962 को भारत रक्षा अध्यादेश (1962 का चौथा) जारी किया। अध्यादेश के अनुसार, केंद्र सरकार को भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश के रखरखाव या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन या आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 5 नवंबर, 1962 को आधिकारिक राजपत्र,

असाधारण में अधिसूचना द्वारा भारत रक्षा नियम, 1962 को लागू किया। आर 30 का प्रासंगिक भाग। यह इस प्रकार हैः

> "केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में यह संतुष्ट है कि उसे भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों, भारत के किसी भी हिस्से में शांतिपूर्ण स्थितियों को बनाए रखने या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह एक आदेश दे सकती हैः-
>
> x x
>
> (ख) निर्देश देना कि उसे हिरासत में लिया जाए;
>
> x x x"

आपातकाल की घोषणा के संचालन के दौरान, राष्ट्रपति ने 3 नवंबर, 1962 को निम्नलिखित आदेश जारी किया, जिसमें कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गय, संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत।

> "संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति का किसी भी अदालत में जाने का अधिकार उस अवधि के लिए निलंबित रहेगा, जिसके दौरान 26 अक्टूबर 1962 को अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत जारी आपातकाल की घोषणा लागू

है, यदि ऐसा व्यक्ति भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 (1962 का 4) या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित रहा है।"

आर 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारत रक्षा नियमों के अनुसार, त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने 20 नवंबर, 1962 को याचिकाकर्ता के संबंध में हिरासत का आदेश जारी किया।

"अध्यक्ष आयोग का एफ. सं. 22 (59)-

पी. डी./62 त्रिपुरा प्रशासन कार्यालय।

अगरतला,

20 नवंबर, 1962

आदेश

जहाँ तक मुझे संतोष है कि सुतारमुरा पी. एस. बिसलगर के श्री बिपुल उपनाम मोहन चौधरी पुत्र श्री बिमला चरण चौधरी को हिरासत में लिया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों और त्रिपुरा में शांतिपूर्ण परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य आदेशने से रोका जा सके।

इसलिए अब, उपरोक्त नियमों के नियम 2 के उपनियम (11) के साथ पठित भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि उपरोक्त व्यक्ति को अगले आदेश तक अगरतला की केंद्रीय जेल में रखा जाए।

एस. डी/- (एस. पी. मुखर्जी)

मुख्य आयुक्त, त्रिपुरा "।

त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के 3 दिसंबर, 1962 के आदेश के बाद, याचिकाकर्ता को अगरतला केंद्रीय जेल से हजारीबाग केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। आदेश इन शब्दों में हैः

"त्रिपुरा प्रशासन

गृह विभाग

एफ सं. 22

(59)- पीडी/62

अगरतला,

3 दिसंबर, 1962

अग्रयान 12, 1884

आदेश

भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 30 के उप- नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे उक्त नियमों के नियम 2 के उप- नियम (11) के साथ पढ़ा जाता है और उस संबंध में सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि बिशालगढ़ पी. एस. के सुतारमुरा के एल. बिमला चरण चौधरी के पुत्र श्री बिपुल चौधरी उपनाम मोहन को अगले आदेश

तक उस जेल में निरोध के लिए अगरतला केंद्रीय जेल से हजारीबाग केंद्रीय जेल, बिहार में स्थानांतरित किया जाए।

2. उपरोक्त निरोधित लोगों को इस क्षेत्र से ऊपर उल्लिखित स्थान पर हटाने के लिए बिहार सरकार की सहमति प्राप्त की गई है (उनके तार संख्या 940 राजनीतिक विशेष, दिनांक 1 दिसंबर 1962 के माध्यम से)।

एस. डी/- (एस. पी. मुखर्जी)

मुख्य आयुक्त, त्रिपुरा "।

इस बीच, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी नजरबंदी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए एक याचिका दायर की थी, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यह याचिका 30 नवंबर की है। 1962, जबकि याचिकाकर्ता अभी भी अगरतला केंद्रीय जेल में था। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका त्रिपुरा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तुरंत इस न्यायालय को नहीं भेजी गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता ने केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए बिहार की हजारीबाग केंद्रीय जेल से 15 दिसंबर, 1962 ,18 दिसंबर, 1962 को एक याचिका भेजी। उस याचिका में, अपनी नजरबंदी के तथ्यों को बताते हुए, उन्होंने कहा कि अगरतला केंद्रीय जेल में नजरबंदी के दौरान, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी और इसे इस अदालत में नहीं भेजा गया था और इसे रोक दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगरतला केंद्रीय जेल के जेलर ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि याचिका त्रिपुरा प्रशासन को यह पता लगाने के लिए भेजी गई थी कि क्या वास्तव में एक रिट याचिका भारत के रक्षा नियमों के तहत

है। जब यह याचिका 28 जनवरी, 1963 को इस न्यायालय के समक्ष रखी गई, तो इस न्यायालय ने विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस का पालन करते हुए केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा के न्यायिक सचिव श्री एस. सी. मजूमदार ने इस आशय का एक शपथ पत्र दिया कि उन्होंने उस मामले में भाग लिया था जो नोटिस का विषय था और उनका इस न्यायालय के अधिकार की अवहेलना या अवज्ञा करने का जरा भी इरादा नहीं था। उन्होंने आगे अपनी ओर से त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त की ओर से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने 30 नवंबर, 1962 के अनुच्छेद 32 के तहत मूल याचिका भी पेश की और कहा कि जब भारत के रक्षा नियमों और 3 नवंबर, 1962 के राष्ट्रपति के आदेश पर विचार करते हुए उनके समक्ष याचिका रखी गई थी, तो उन्होंने यह विचार रखा कि याचिका विचारणीय नहीं थी और इसलिए, "कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। "उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और सरकारी वकील के परामर्श के बाद महसूस किया कि सरकार को यह तय करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी कि याचिका विचारणीय है या नहीं और इसे इस अदालत में भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा प्रशासन को दी गई सलाह ईमानदारी से दी गई थी और उन्हें इस बात का बेहद खेद है कि उनकी ओर से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप "हमारे प्रशासन की ओर से गलत कार्य होना चाहिए था। "जब मामला इस न्यायालय के समक्ष रखा गया, तो खण्ड पीठ ने 18 फरवरी, 1963 के अपने आदेश द्वारा श्री एस. सी. मजूमदार की ओर से बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और आगे निर्देश दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को प्रारंभिक सुनवाई के लिए रखा जाए। इसके बाद संविधान पीठ ने 27 मार्च, 1963 के अपने आदेश में नियम जारी करने और 10 दिनों के भीतर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। चूंकि याचिकाकर्ता सुनवाई में पेश हुआ था, इसलिए यह निर्देश दिया गया कि उसे रिट याचिका के निपटारे तक दिल्ली जेल में रखा जाए। जब मामला अंतिम सुनवाई के लिए हमारे सामने आया, तो हमने निर्देश

दिया कि इसमें शामिल महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को देखते हुए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व हमारे सामने वकील द्वारा किया जाए। श्री आर. के. गर्ग ने इस मामले पर बहुत पीड़ा झेली है और हमारे सामने सभी संभावित विचार रखे हैं जिनके लिए न्यायालय उनके प्रति बाध्य है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। प्रतिवादी, मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा की ओर से कारण दिखाएँ। हमने दोनों पक्षों के वकीलों को पूरी तरह से सुना है। सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में लिए गए श्री राज कुमार वोहरा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसी तरह की एक रिट याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। चूंकि उनकी याचिका में उठाए जाने वाले बिंदु वर्तमान याचिका के समान बताए गए थे, इसलिए हमने हस्तक्षेप की अनुमति दी।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने योग्यता के आधार पर रिट याचिका की सुनवाई के लिए प्रारंभिक आपत्ति ली है, इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने अनुछेद के तहत अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया है। 21 और संविधान की धारा 22, अपने 3 नवंबर, 1962 के आदेश द्वारा, जिसे विस्तार से ऊपर उद्धृत किया गया है, याचिकाकर्ता अपने द्वारा दावा किए गए अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है। इस प्रारंभिक आपत्ति के जवाब में, श्री गर्ग ने जोरदार तर्क दिया है कि अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अनुच्छेद अधिकारों के प्रयोग के निलंबन को अधिकृत नहीं करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में जाने का अधिकार, जो स्वयं एक गारंटीकृत अधिकार है, राष्ट्रपति के उपरोक्त आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया गया है और इस न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने वाला आदेश इस शर्त पर निर्भर करता है कि एक वैध अध्यादेश और नियम बनाए गए थे और उसके तहत आदेश दिया

गया था। इसके अलावा तर्क यह है कि पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं की गई है क्योंकि अध्यादेश (1962 का चौथा) ने विधायी क्षमता के अभाव में अमान्य होने के अलावा, अधिनियम (1962 का एल. आई.) द्वारा इसे निरस्त करने पर अपना बल खर्च किया है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि हमले से प्रतिरक्षा, यदि बिल्कुल भी हो, केवल अध्यादेश के तहत किए गए किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध होगी, लेकिन क्योंकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोई नया आदेश नहीं था, अध्यादेश के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को विवाद के गुण- दोष में जाने का अधिकार था और यह दिखा सकता था कि भारत रक्षा अधिनियम असंवैधानिक था और इसके तहत बनाए गए नियम समान रूप से थे। हमारी राय है कि प्रारंभिक आपत्ति अच्छी तरह से आधारित है। तदनुसार हमने पक्षकारों को सूचित किया कि न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति की वैधता को स्वीकार करने के बाद मामले के गुण-दोष पर सुनवाई करने का प्रस्ताव नहीं किया है और उस निष्कर्ष पर आने के हमारे कारण बाद में दिए जाएंगे। अब हम उस निष्कर्ष के लिए अपने कारण बताते हैं।

संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए इस न्यायालय में जाने का अधिकार अपने आप में एक गारंटीकृत अधिकार है। लेकिन सी. एल. (4) अनुच्छेद 32 स्वयं यह प्रावधान करता है कि इस प्रकार की गारंटी वाले अधिकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। हमने एक सकारात्मक रूप में कहा है कि सी. एल. द्वारा नकारात्मक रूप में क्या प्रदान किया गया है। सी. एल. (4), जो इस प्रकार चलता हैः

> "इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा निलंबित नहीं किया जाएगा।"

अब अनुच्छेद 32 के उक्त खंड को ध्यान में रखते हुए संविधान द्वारा क्या प्रावधान किया गया है? 26 अक्टूबर, 1962 को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुच्छेद 19 के प्रावधान, विभिन्न स्वतंत्रताओं को निर्धारित करते हैं, जिन्हें सभी नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार है, इस परिणाम के साथ निलंबित कर दिया जाता है कि कोई भी कानून बनाने या कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति तब तक बाधित नहीं होती है जब तक कि घोषणा जारी रहती है (अनुच्छेद 358) दूसरा, उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 (1) द्वारा संविधान के भाग III में निहित मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के आदेश द्वारा सशक्त किया गया है। 3 नवंबर, 1962 का राष्ट्रपति का आदेश पहले ही निर्धारित हो चुका है। संदर्भ में, कला द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति के किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, आपातकाल की अवधि के दौरान, इसलिए, प्रथमदृष्टया, याचिकाकर्ता का बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए इस न्यायालय का रुख करने का अधिकार, जैसा कि उसने इस याचिका द्वारा करने का इरादा किया है, आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 359 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत अधिकार के प्रयोग के निलंबन को अधिकृत नहीं करता है, और यह कि, संदर्भ में, अनुच्छेद 32 के संचालन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया गया है। यह तर्क पूरी तरह से निराधार है। निर्विवाद रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट जारी करने की न्यायालय की शक्ति को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा छुआ नहीं गया है, लेकिन अनुच्छेद 359 (1) के तहत पारित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस तरह के रिट के लिए इस न्यायालय में जाने के याचिकाकर्ता के अधिकार को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति का आदेश किसी नागरिक को इस न्यायालय में जाने के लिए निहित सभी

अधिकारों को निलंबित नहीं करता है, बल्कि केवल कला के प्रावधानों को लागू करने का उसका अधिकार है। इस प्रकार, राष्ट्रपति के आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का इस न्यायालय में जाने का अधिस्थिति, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की शक्ति को नहीं, आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को आपातकाल के दौरान अपने अधिस्थिति, यदि कोई हो, को लागू करने का कोई अधिस्थिति नहीं है।

यह भी तर्क दिया गया कि 3 नवंबर, 1962 का राष्ट्रपति का आदेश इस शर्त के अधीन है कि एक वैध अध्यादेश है और बनाए गए नियम या उसके तहत दिए गए आदेश वैध हैं। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता अध्यादेश की वैधता का प्रचार करने के लिए खुला है। यह एक घेरे में बहस कर रहा है। ताकि न्यायालय किसी विशेष अध्यादेश या विधायिका के अधिनियम की वैधता की जांच आदेश सके, न्यायालय का रुख आदेशने वाले व्यक्ति का अधिस्थिति होना चाहिए। यदि उसके पास न्यायालय का रुख करने का अधिस्थिति नहीं है, तो न्यायालय विशेष विधान के अधिस्थितिों पर सवाल उठाने वाली उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर देगा। संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के प्रावधानों के तहत पारित राष्ट्रपति के आदेश को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने आपातकाल की अवधि के दौरान इस न्यायालय का रुख करने का अपना अधिस्थिति खो दिया है जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। ऐसा होने पर, यह याचिका विचारणीय नहीं है।

लेकिन विकल्प में यह तर्क दिया गया है कि यह मानते हुए कि अध्यादेश वैध है और राष्ट्रपति का आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ काम करता है, राष्ट्रपति के आदेश में अंतिम खंड के शब्द, "यदि ऐसा व्यक्ति" से शुरू होते हैं, तो पूरा नहीं होते हैं क्योंकि अध्यादेश को अधिनियम (1962 का एल. आई.) द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। सवाल, वहाँ सामने आता हैः इन शब्दों का क्या प्रभाव है?विद्वान

महान्यायवादी ने अपने तर्क को दो वैकल्पिक तरीकों से रखा है। सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि वे शब्द उस व्यक्ति के बारे में वर्णनात्मक थे जिसे हिरासत में लिया गया है और यह नहीं कि वे एक पूर्ववर्ती शर्त रखते हैं, जैसा कि परिवेदक की ओर से तर्क दिया गया है, प्रथमदृष्टया इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है लेकिन हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम वर्तमान में वैकल्पिक तर्क पर पहुंचे हैं। वैकल्पिक रूप से उन्होंने तर्क दिया कि, एस के तहत सामान्य खंड अधिनियम (1897 का X), अधिनियम (1962 का एल. आई.) की धारा 48, जो 1962 के अध्यादेश 4 और 6 को निरस्त करती है और जो उन अध्यादेश के तहत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई को बचाती है, का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि आर. के तहत किए गए निरोध आदेश को जारी रखा जा सके। भारत के रक्षा नियमों का, उस अध्यादेश के निरसन के बाद भी जिसके तहत उन्हें प्रख्यापित किया गया था। खंड 48 इन शब्दों में हैः

> "48 (1). भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 और भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1962, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।
>
> (2) इस तरह के निरसन के बावजूद, भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1962 द्वारा संशोधित भारत रक्षा अध्यादेश, 1962 के तहत बनाए गए किसी भी नियम, कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तहत की गई, की गई या की गई मानी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम 26 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था।"

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उप- धाराओं के आधार पर। (2) धारा 48, ऊपर उद्धृत, याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित निरोध आदेश को भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत किया गया माना जाएगा, और इसलिए, 3 नवंबर, 1962 का

राष्ट्रपति का आदेश, जिसमें भारत रक्षा अध्यादेश और उसके तहत नियमों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित निरोध आदेश का संदर्भ है, पूरी तरह से निष्क्रिय था। उपरोक्त अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा तब जारी किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। उनके पास संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव था, लेकिन वे संसद की पुनः सभा से 6 सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर देंगे। यदि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में विशेष उपायों को जारी रखना है, तो आवश्यक रूप से अधिनियम को उस अवधि के भीतर अध्यादेश का स्थान लेना होगा। इसलिए, संसद को उपरोक्त अध्यादेश 4 और अध्यादेश 6 के समान प्रावधानों को परिणामी परिवर्धन और परिवर्तनों के साथ अधिनियमित करना पड़ा। भारत रक्षा अधिनियम (1962 का एल. आई.) स्वयं प्रस्तावना में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा और सार्वजनिक सुरक्षा और हित सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों का प्रावधान करने की आवश्यकता का पाठ करता है। यह अधिनियम 12 दिसंबर, 1962 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत, उपरोक्त अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन सभी कार्रवाई और उसके तहत बनाए गए सभी नियमों को इस कल्पना को लागू करके जारी रखा गया है कि उन्हें अधिनियम के तहत बनाया या लिया गया माना जाएगा, जो 26 अक्टूबर, 1962 को शुरू हुआ माना जाता है, जिस तारीख को अध्यादेश 4 लागू किया गया था। 3 नवंबर, 1962 का राष्ट्रपति का आदेश, कला के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों को निलंबित करता है। 21 और संविधान का 22, तब बनाया गया था जब 1962 का 4 का अध्यादेश लागू था, और इसलिए, तथ्यों पर ध्यान दें था क्योंकि वे तब मौजूद थे। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8 (1), जो अधिनियम (1962 का एल. आई.) के निर्माण पर लागू होती है, इन शब्दों में हैः

> "8(1) जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, पूर्व अधिनियम के

किसी प्रावधान को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निरस्त और पुनः अधिनियमित करता है, तो किसी अन्य अधिनियम में या इस तरह से निरस्त किए गए प्रावधान के किसी भी साधन में संदर्भ, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, इस तरह से फिर से अधिनियमित प्रावधान के संदर्भों के रूप में माने जाएंगे।"

क्या उपरोक्त प्रावधान 3 नवंबर, 1962 के आदेश के निर्माण पर लागू होते हैं, जिसे राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता के इस न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करते हुए पारित किया था? यह प्रतिवाद नहीं किया गया है कि वे प्रावधान अधिनियम (1962 का एल. आई.) के निर्माण पर लागू होते हैं, जो उपरोक्त अध्यादेश के प्रावधानों को निरस्त और फिर से लागू करते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या वे राष्ट्रपति के आदेश के निम्नलिखित शब्दों को समझने में उपलब्ध हैं।

"यदि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में रक्षा अध्यादेश, 1962 (1962 का 4) या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है।"

क्या विचाराधीन राष्ट्रपति का आदेश धारा के अर्थ के भीतर एक "साधन" है? सामान्य खंड अधिनियम "साधन" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है। इसलिए, अभिव्यक्ति का उपयोग उस अर्थ में किया जाना चाहिए जिसमें इसे आम तौर पर कानूनी भाषा में समझा जाता है। स्ट्राउड के जुडिशल डिक्शनरी ऑफ वड्र्स एंड फ्रेज़ेस (तीसरा संस्करण, 455 खंड 2, पृष्ठ 1472) में, "इंस्ट्रूमेंट" का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

"'एक 'उपकरण' एक लेखन है, और आम तौर पर एक औपचारिक कानूनी प्रकार के दस्तावेज़ का आयात करता है। कुल मिलाकर, इस

शब्द में संसद का एक अधिनियम शामिल हो सकता है। (11) परिवहन अधिनियम, 1881 (41, 44 और 45), धारा 2 (xiii), 'लिखत' में विलेख, वसीयत, समावेशन, पुरस्कार और संसद का अधिनियम शामिल है।"

अभिव्यक्ति का उपयोग एक विलेख अंतर- पक्ष या एक चार्टर या एक रिकॉर्ड या औपचारिक प्रकृति के अन्य लेखन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन सामान्य खंड अधिनियम के संदर्भ में, इसे एक औपचारिक अधिनियमी लेखन जैसे कि एक क़ानून या अधीनस्थ अधिनियम के तहत किए गए आदेश या संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण के तहत बनाए गए औपचारिक चरित्र के किसी भी दस्तावेज़ के संदर्भ को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि धारा 8 में अभिव्यक्ति "उपकरण" है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए आदेश का संदर्भ शामिल करना था। इस प्रकार राष्ट्रपति का आदेश, उपरोक्त अध्यादेश के निरसन के बाद भी आर 30 के तहत किए गए निरोध के मामलों को नियंत्रित करना जारी रखेगा। अध्यादेश के तहत उपरोक्त। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि इस तर्क में कोई सार नहीं है कि मूल रूप से अध्यादेश के तहत नियम के तहत याचिकाकर्ता की नजरबंदी को अधिनियम (1962 का एल. आई.) के तहत जारी नहीं माना जाएगा। समान रूप से स्पष्ट रूप से, इस तर्क में कोई सार नहीं है कि अधिनियम के अधिनियमन के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसी आदेश को दोहराया जाना चाहिए था। यह सरासर अतिविचार और धारा 8 में निर्धारित कानूनी कल्पना का कार्य होता। इसका उद्देश्य संवैधानिक तंत्र के उपयोग के इस तरह के अनावश्यक दोहराव से बचना है। अधिनियम की धारा 48, के प्रावधानों का उचित निर्माण जिसने उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है, धारा 8 के प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाता है। सामान्य खंड अधिनियम इस बात में कोई

संदेह नहीं छोड़ता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित निरोध आदेश का उद्देश्य अधिनियम (1962 का एल. आई.) में शामिल अध्यादेश के निरसन के बाद भी जारी रखना था। ऐसा होने पर, राष्ट्रपति के आदेश का संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए इस न्यायालय में जाने के याचिकाकर्ता के अधिकार को निलंबित करने का प्रभाव होना चाहिए। याचिकाकर्ता के कुछ समय के लिए इस न्यायालय में जाने के अपने अधिकार से वंचित होने के बाद, यह स्पष्ट है कि वह अध्यादेश या उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधिकार के संबंध में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। नतीजतन, आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है, और इसलिए, खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।